



# जनजाति समाज के लिए चलाई जा रही आर्थिक विकास की योजनाएं



प्रह्लाद सबनानी

जनजाति समाज के लिए  
केंद्र सरकार द्वारा पलाई जा  
रही विभिन्न योजनाओं को  
दो प्रकार से घलाया जा रहा  
है। कई योजनाओं का

सीधा लाभ जनजाति समाज के सदस्यों को प्रदान किया जाता है। साथ ही, कुछ योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा शिशेष क्रेंटीय

सहायता एवं अनुदान प्रदान किया जाता है और इन योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। जैसे

जनजातीय उप-योजना के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनजातीय विकास हेतु किए गए प्रयासों को पूरा करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

**ज** नजाति समाज बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए देश में दूर दराज इलाकों के सघन जंगलों के बीच वनों में रहता है। नजाति समाज के सदस्य बहुत ही कठिन जीवन व्यतीत करते रहे हैं एवं देश के वनों की सुरक्षा में इस समाज का योगदान अतुलनीय रहा है। चूंकि यह समाज भारत के सुदूर इलाकों में रहता है अतः देश के अर्थिक विकास का लाभ इस समाज के समाजमें से एक भी निकलता रहा है। उनीं सार्वजनिक सेवा के लिए जिसका अप्पा नाम है।

समाज के सदस्यों का कम हा मिलता रहा ह। इसा सदर्भ में केंद्र सरकार एवं कई राज्य सरकारों ने विशेष रूप से जनजाति समाज के लिए कई योजनाएं इस उद्देश्य से प्रारम्भ की हैं कि इस समाज के सदस्यों को राष्ट्र विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके एवं इस समाज की कठिन जीवनशैली को कुछ हद तक आसान बनाया जा सके। भारत में सम्पन्न हुई वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। जनजाति समाज के सदस्यों को भारतीय राजनीति की मुख्यधारा में शामिल किए जाने के प्रयास भी किए जाते रहे हैं एवं इस समाज के कई प्रतिभाशाली सदस्य तो कई बार केंद्र सरकार के मंत्री, राज्यपाल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के पदों तक भी पहुंचे हैं। आज भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्वापटी मुर्मु भी अदिवासी समाज से ही आती हैं।

केंद्र सरकार द्वारा जनजाति समाज को केंद्र में रखकर उनके लाभार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से एक विशेष पोर्टल का निर्माण किया है। जिसकी लिंक है - भारत सरकार का राष्ट्रीय पोर्टल <https://www.ईडिया.सरकार.भारत/> - इस लिंक को क्लिक करने के बाद 'योजे' के बॉक्स में जनजाति समाज को दी जाने वाली सुविधाएं टाइप करने से, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं की सूची निकल आएगी एवं इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रपत्रों की सूची भी डाउनलोड की जा सकती है।

जनजाति समाज के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को दो प्रकार से चलाया जा रहा है। कई योजनाओं का सीधा लाभ जनजाति समाज के सदस्यों को प्रदान किया जाता है। साथ ही, कुछ योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को विशेष केंद्रीय सहायता एवं अनुदान प्रदान किया जाता है और इन योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। जैसे, जनजातीय उप-योजना के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनजातीय विकास हेतु किए गए प्रयासों को पूरा करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता का मूल प्रयोजन पारिवारिक आय सृजन की निम्न योजनाओं जैसे कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, पशुपालन, वन, शिक्षा, सहकरिता, मत्स्य पालन, गांव, लघु उद्योगों तथा न्यूनतम आवश्यकता संबंधी कार्यक्रमों से है। इसी प्रकार, जनजातीय

विकास हेतु परियोजनाओं की लागत को पूरा करने तथा अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन स्तर को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी अनुदान दिया जाता है। जनजातीय समाज के विद्यार्थियों के गुणवत्ताप्रक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करने हेतु भी उक्त निधियों के कुछ हिस्से का प्रयोग किया जाता है।

राज्य संस्कारा का वित्त उपलब्ध कराने सम्बंधी उक्त दो योजनाओं का केवल उदाहरण के लिए वर्णन किया गया है। अन्यथा इसी प्रकार की कई योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में जनजाति समाज के सदस्यों को सीधे ही लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से भी केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं— (1) आदिवासी उत्पादों और उत्पादन विपणन-विकास की योजना; (2) एमएसपी योजना की मूल्यविश्वंखला के विकास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनापज के विपणन हेतु योजना; (3) आदिवासी उत्पादों या निर्माण योजना के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायोग की योजना; (4) आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना; (5) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की योजना; (6) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए अनुदान योजना; (7) उत्कृष्ट केन्द्रों के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता योजना जिसका लाभ जनजातीय विकास और अनुसंधान क्षेत्र में काम कर रहे विश्वविद्यालयों और संस्थानों को दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की संस्थागत संसाधन क्षमताओं को बढ़ाना और मजबूत बनाना है ताकि इन अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालय के विभागों द्वारा आदिवासी समुदायों पर गुणात्मक, किया उन्मुख और नीति अनुसंधान का संचालन किया जा सके; (8) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) और राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एसटीएफडीसी) के न्यायसम्य (इक्विटी) सहायता प्रदान करने की योजना। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और आदिवासी विकास के मामले में मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है; (9) आदिवासी आवासीय विद्यालयों की स्थापना सम्बंधी योजना; (10) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के छात्रवृत्ति योजना; (11) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के योग्यता उन्नयन संबंधी योजना; (12) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना। उक्त समस्त योजनाओं की विस्तृत जानकारी उक्त वर्णित पर्टेल्स पर उपलब्ध है।

इसी प्रकार केंद्र सरकार के साथ साथ कई राज्य सरकारें भी जनजाति समाज के लाभार्थ स्वतंत्र रूप से कुछ योजनाओं का संचालन करती है। मध्यप्रदेश, भारत के आदिवासी

बहुल क्षेत्रों में गिना जाता है एवं मध्यप्रदेश में विविध, समझुआ एवं गौरवशाली जनजातीय विरासत है जिसका विविध मध्यप्रदेश में न केवल संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है, अपितु जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास तथा जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कई प्रकार के कार्य भी किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या की 14.64% जनसंख्या निवास करती है। आज में 12 तक 15 वर्ष की उम्र के बीच

करता है। भारत में 10 करोड़ 45 लाख जनजाति जनसंख्या है, वहाँ मध्यप्रदेश में 01 करोड़ 53 लाख जनजाति जनसंख्या है। भारत की कुल जनसंख्या में जनजातिवाले जनसंख्या का प्रतिशत 8.63 है और मध्यप्रदेश में कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 21.09 है। मध्यप्रदेश में जनजाति उपर्योगिना क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का 30.19% है। प्रदेश में 26 वृहद, 5 मध्यम एवं 6 लहर जनजाति विकास परियोजनाएं संचालित हैं तथा 30 माड़ पॉकेट हैं। मध्यप्रदेश में कुल 52 जिलों में 21 आदिवासी जिले हैं, जिनमें 6 पूर्ण रूप से जनजाति बहुल जिले तथा 15 अशिक जनजाति बहुल जिले हैं। मध्यप्रदेश में 83 जनजाति विकास खंड हैं। मध्यप्रदेश के 15 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया के 11 विशेष पिछड़ी जाति समूह अभिकरण संचालित हैं।

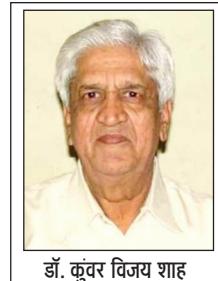
मध्यप्रदेश सरकार जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक विकास के साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न कल्याणकार्यों योजनाएं संचालित कर रही हैं। (1) मध्यप्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल 15 जिलों में आहार अनुदान योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों की महिला मुखिया के बैंक खते में प्रतिमाह रु. 1000 की राशि जमानी की जाती रही है। (2) आकंक्षा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 11वीं एवं 12वीं कक्षा वेद्य प्रतिभावान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जईई, नीट, क्लेट की तैयारी के लिए निःशुल्क कार्यिंग एवं छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है। (3) प्रतिभावान योजना के अंतर्गत जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शासकीय शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। (4) आईआईटी, एम्स, क्लेट तथा एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर रूप 50 हजार रुपए की राशि तथा अन्य परीक्षाओं जईई, नीट एनआईआईटी, एफडीडीआई, एनआईएफटी, आईएचएपी के माध्यम से प्रवेश लेने पर रु. 25 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती रही है। (5) महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी गृह नगर से बाहर अन्य शहरों में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें वहाँ आवास के लिए संभाग स्तर पर 2000 रुपए, जिला स्तर पर 1250 रुपए तथा विकास खंड एवं तहसील स्तर पर 1000 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता, आवास सहायता योजना वे



अंतर्गत प्रदान की जाती रही है। (6) इसी प्रकार की सहायता अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विदेश स्थित उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन के लिए भी प्रदान की जाती है। (7) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए प्रदेश के 89 जनजाति विकास खंडों में प्राथमिक शालाओं से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर की शालाएं संचालित की जा रही हैं जिनमें विद्यार्थियों का प्री-मेट्रिक तथा पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति दी जा रही है। (8) मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति के ऐसे विद्यार्थियों, जो सिविल सेवा परीक्षा में निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही अनुसूचित जनजाति के प्रदेश के ऐसे विद्यार्थी, जो सिविल सेवा परीक्षा की प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें 40 हजार रुपए, जो मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं उन्हें 60 हजार रुपए तथा साक्षात्कार सफल होने पर 50 हजार रुपए की राशि दी जाती रही है। (9) मध्यप्रदेश में जनजातीय लोक कलाकृतियों एवं उत्पादों को लोकप्रिय करने तथा उनसे जनजाति वर्ग को लाभ दिलाए जाने के उद्देश्य से उनकी जी आई ट्रैटिंग कराई जा रही है। प्रथम चरण में 10 जनजाति लोक कलाकृतियों एवं उत्पादों की जी आई ट्रैटिंग कराए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इस प्रकार, केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जनजाति समाज के लाभार्थ अन्य कई प्रकार की विशेष योजनाएं सफलता पूर्वक चलाई जा रही हैं ताकि जनजाति समाज की कठिन जीवन शैली को कुछ आसान बनाया जा सके एवं जनजाति समाज को देश की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके।

संपादकीय

# बुलडोजर पर लक्षण रेखा



**स** वैच्च न्यायालय के एक फैसले ने आज पुनः सिद्ध कर दिया है कि प्रजातंत्र के चार अंगों- विधायिका, कार्यपालिका, न्याय पालिका और खबर पालिका में न्याय पालिका ही प्रजातंत्र की सही संरक्षक है, कथित अवैध निर्माणों के नाम पर लोगों के घरों को 'जर्मिंदोज' कर देने की शासकीय मनमानी पूर्ण प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय ने एकदम गैर कानूनी व गलत माना है तथा शासन-प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना ठोस गैरकानूनी सबूतों के ऐसी कार्यवाही करतई नहीं की जानी चाहिए। इस तरह आज फिर एक बार यह स्पष्ट हो गया है कि प्रजातंत्र की सही संरक्षक न्यायपालिका ही शेष बची है, प्रजातंत्र के शेष अंग विधायिका, कार्यपालिका और खबर पालिका अब अपने कर्तव्यों मंसूबों, अधिकारों व कार्यों के प्रति ईमानदार करतई नहीं रहे हैं, इसीलिए आज आम भारतीय का विश्वास सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका पर ही केन्द्रित हो गया है।

**र प्रमाणित- न्यायपालिका हीं प्रजातत्र को सही सरक्षक....!**



प्रजातंत्र के अंगों में प्रमुख तौर पर विधायिका की भूमिका अहम् मानी जाती रही है, किंतु अब इस अंग में स्वार्थ की राजनीति इतनी अधिक हावी हो गई है कि इसने आप जनप्रतिनिधि को जनसेवा के मार्ग से बिल्कुल अलग कर दिया है, आज तो इस अंग में यह धारणा समाहित हो गई है कि किसी भी तरह के कानूनी या और कानूनी हथकड़ों का सहारा लेकर एक बार सांसद या विधायक बन जाओं और फिर अपने आपको अगली सात पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखने की क्षमता हासिल कर लो, और अब यही हो रहा है, एक बार येन-केन-प्रकारण सांसद, विधायक चूने जाने के बाद फिर राजनेता 'जनसेवा' भूलकर

'स्वयंसेवा' में संलग्न हो जाते हैं और पांच साल सत्ता की लूट के सहारे अपने भविष्य को सपरिचिनी 'स्वर्णिम' बना लेते हैं और उन्हें इस स्थान पहुंचाने वालों को पूरी तरह बिसरा देते हैं, फिर इन याद अगले चुनाव अर्थात् पांच साल बाद ही आती है। यह तो हुआ प्रजातंत्र के सबसे अहम् अंग विधायिका का हाल, अब यदि दूसरे अंग कार्यपालिका की तरफ करें तो मेरी दृष्टि में उसका नाम कार्यपालिका बदलकर 'जी-हुजूरी पालिका' रख देना चाहिए। क्योंकि इस अंग से जुड़े सरकारी अमला जनसेवा के मूल दायित्वा को त्याग कर सिर्फ विधायिका के सदस्यों (राजनेताओं) व उनके समर्थकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

# प्रदूषण: जटिल होता जा रहा समाधान

पिछले दिनों पड़ोसी पाकिस्तान से ऐसी खबर आई जिसने काफी चिंता बढ़ाई। पाकिस्तान के लाहौर शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स ने 2000 का आंकड़ा छू लिया। इसके चलते वहाँ के प्रशासन ने जेनभलाई के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने बढ़ते प्रदूषण के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। परली जलाए जाने की समस्या हर वर्ष प्रदूषण का कारण बनती है। हर वर्ष बड़ी-बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते। इस वर्ष भी वायु प्रदूषण के आंकड़े चिंताजनक स्थिति तक पहुंच गए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा कभी भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसमें निर्माण कार्य पर रोक लगाना, भवनों की तोड़-फोड़ पर रोक लगाना, पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर रोक लगाना और कुट्टा जलाने पर रोक लगाना आदि उपाय शामिल हैं। निर्माण कार्यों पर रोक लगाना तो समझ में आता है परंतु जिन पुराने वाहनों पर रोक लगाती है, उससे सरकार को क्या हासिल होता है, वह समझ नहीं आता।

यदि आपका वाहन दस साल से अधिक पुराना है, और उसमें वैध पीयूसी सर्टिफिकेट है, तो आपका वाहन प्रदूषण के तथ यानिकों की सीमा में ही खुआ न यानी आपका वाहन अनियंत्रित प्रदूषण नहीं कर रहा। इसके बावजूद अपनी गाड़ियों में नियमित 'पीयूसी' जांच करवाने वालों को प्रतिबंध के चलते वाहन सड़क पर लाने की इजाजत नहीं दी जाती। क्या यह उचित है? कोई उपभोक्ता एक-एक पाई जोड़ कर अपने सपनों का वाहन खरीदता है, तो उसे रोड टैक्स, जीएसटी आदि टैक्स भी देने पड़ते हैं। इन सब टैक्सों

का मतलब है कि यह सब राशि सरकार की जेब जाएगी और धूम कर जनता के विकास के लिए इस्तेमाल की जाएगी परंतु रोड टैक्स के नाम पर जाने वाली मोटी रकम क्या वास्तव में जनता पर रहती है? क्या हमें अपनी महंगी गाड़ियों को चलाने लिए साफ-सुधरी और बेहतरीन सड़कें मिलती क्या टूटी-फूटी सड़कों की समय से मरम्मत होती अधिकतर सवालों के जवाब आपको न में ही मिलें टूटी-फूटी सड़कों पर वाहन अवरोधों के साथ चल पर मजबूर होते हैं, नतीजा होता है जगह-जगह ट्रैफिक जाम। जाम में खड़े रह कर आप न सिर्फ सभी जाया करते हैं, बल्कि महंगा ईंधन भी जाया करते हैं देर तक जाम लगा रहेगा, वाहन बंपर-टूंबंपर चलते बढ़ते प्रदूषण की आग में घी का काम करेगा। में जिन वाहनों को पुराना समझ कर प्रतिबंधित विजाता है, उनसे कहीं जयादा मात्रा में नये वाहनों प्रदूषण होता है। इसलिए लोक निर्माण विभाग या उपर्याईयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सड़कों तुरुस्त रखें ताकि प्रदूषण को बढ़ावा न मिले। सरकार द्वारा वाहनों के प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण रखने की दृष्टि से कई नियम लागू किए गए हैं। इसे अहम है दस साल पुराने डीजल और पंद्रह वर्ष अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को महानगरों की सड़क पर चलने की अनुमति न देना। इसके साथ ही जिन वाहनों को चलने की अनुमति है, उन सर्वधैर्य वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी 'पीयूसी' है अनिवार्य है। सीधा मतलब यह कि आपके वाहन वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हैं तो आपके वाहन मानकों से अधिक प्रदूषण नहीं कर रहा है, और त



ऐसे नया द्वारा अन्य को त्रित नमें रुप से उकों नन- में गीना न में तय तभी आपके वाहन को सड़क पर अने की अनुमति है। हर वर्ष नवम्बर के महीने में दिल्ली सरकार अपने आदेश के तहत बिना पीयूसी चलने वाले वाहनों पर 10,000 रुपये का मोटा जुमारा लगाने के आदेश जारी कर देती है। इसका पालन भी सख्ती से होता दिखाई देता है। पर्यावरण विशेषज्ञ, नेता और संबंधित सरकारी विभागों के अफसर इस बार भी इस समस्या को लेकर सिर खपा रहे हैं। उन्होंने सोच-विचार का नतीजा बताया है कि फसल कटने के बाद जो ठूंठ बचते हैं, उन्हें खेत में जलाए जाने के कारण यह धुआं बना है जो एनसीआर के ऊपर छा गया है। लैकिन सवाल उठता है कि यह तो हर साल ही होता है तो नये जवाबों की तलाश क्यों हो रही है? सरकार को प्रदूषण की समस्या से छुटकारा पाना है तो उसे असल कारणों पर वार करना होगा।







संक्षिप्त समाचार

**राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार मिले बाइडेन और ट्रंप, सत्ता सौंपने को लेकर हुई चर्चा**



वाशिंगटन, एंजेसी। डानाल्ड ट्रॅप ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बुधवार के व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और इस दोस्रा दोनों नेताओं ने अमेरिकी पंरपरा के तहत सत्त के सहज हस्तांतरण का संकल्प जताया। एक सक्षिप्त बैठक में दोनों नेताओं ने देश को अगत वर्ष 20 जनवरी को शांतिपूर्ण सत्त हस्तांतरण का आश्वासन दिया। बाइडेन ट्रॅप का स्वागत किया और दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। बाइडेन ने ट्रॅप को उनकी जीत पर बधाई दी औं कहा कि वह एक सहज सत्ता हस्तांतरण का आशा करते हैं। ट्रॅप ने कहा, “राजनीति कठिन है और कई मामलों में यह बहुत अच्छी दुनिया है नहीं है, लेकिन आज यह एक अच्छी दुनिया है। यह और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। यह बदलाव बहुत सहज है और यह जितना संभव है उतना सहज होगा।

ईरान ने कई महिलाओं से रेप के दोषी  
को सरेआम फांसी पर लटकाया

तेरहान। पिछले दो दशक में कई महिलाओं ने दुष्कर्म के दोषी एक ईरानी व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया। ईरान के सरकारी मीडिया ने बुधवार का यह जानकारी दी। सरकारी अखबार ने बताया कि देश के उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर के शुरुआत में मोहम्मद अली सलामत की मौत की सजा बरकरार रखी थी जिसके बाद उसे फांसी दे दी गयी। उसे मंगलवार सुबह पश्चिम हमेदान शहर में एक कब्रिस्तान में मौत की सजा दी गयी। करीब 200 महिलाओं ने दवा कंदुकान और एक जिम चलाने वाले 43 वर्षीय सलामत पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। [ऐसे आरोप था कि उसने पिछले 20 वर्ष में कई अपराधों को अंजाम दिया। ईरानी मीडिया में आयी खबरों में कहा गया है कि कई मामलों में सलामत ने महिलाओं को शादी का प्रस्ताव देने के बाद या प्रेम प्रसंग के दौरान उनका दुष्कर्म किया। उसने कुछ महिलाओं को कथित तौर पर गर्भपात की दवाएँ भी दीं जो ईरान में गैरकानूनी है। उसे जनवरी में गिरफतार किया गया था। इसे ईरान में एक अपराधी द्वारा दुष्कर्म के सबसे अधिक अपराध को अंजाम देने का मामला बताया जा रहा है। उसकी गिरफतारी वे बाद सैकड़ों लोग शहर के न्याय विभाग वे सामने एकत्रित हो गए थे और उन्होंने सलामत को फांसी देने की मांग की थी। ईरान में दुष्कर्म और व्यभिचार के लिए मौत की सजा का प्रावधान है।

पाकिस्तान में अक्टूबर से दिसंबर तक  
शादी समारोहों पर लगेगा सख्त बैन



लाहौर , जेंजे सी। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की सरकार ने स्मॉग पर नियंत्रण के लिए एक नई नीति लागू की है, जिसके तहत अब हर साल अक्टूबर से दिसंबर तक शारीर समारोहों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। यह नीति लाहौर हाई कोर्ट में पेश की गई, जिसमें बताया गया कि शादी समारोहों से ट्रैफिक और ऊर्जा की खपत बढ़ती है, जो प्रदूषण में अहम भूमिका निभाती है। पंजाब वेले एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को जानकारी दी कि इस बार पहली बार स्मॉग नियंत्रण वेले लिए विशेष बजट निर्धारित किया गया है। कोर्ट ने इन कदमों की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रशासन पहले की सरकारों से अधिक प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। इस नीति के तहत किसानों को पराली जलाना से रोकने के लिए सुपर सीडर मशीन वितरित की जाएंगी, जो पराली जलाने के बजाय उसे खेत में नष्ट कर देती हैं, जिससे स्मॉग में कमी हो सके। कोर्ट ने सुझाव दिया कि शादी समारोहों में एक व्यंजन का व्यवस्था लागू की जाए और शादी वेले कार्यक्रमों की संख्या भी सीमित की जाए। कोर्ट ने टैक्षिक उदाहरणों का ड्रावला देते हुए

का नरनाल वाशिंगटन, एजेंसी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टीम के चुनाव पर दुनिया को चौका दिया है। उन्होंने पूर्व डेमोक्रेटिक सांसद तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटिलेजेंस डायरेक्टर के पद के लिए नामांकित किया। गबार्ड, जिन्होंने 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की दौड़ में हिस्सा लिया था, अब अपनी राजनीतिक विचारधारा बदल चुकी है और उनके करियर ने दोनों राजनीतिक पार्टियों से समर्थन पाया है। इस नए पद पर गबार्ड अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियों की देखरेख करेंगी। गबार्ड के इस महत्वपूर्ण खुफिया पद पर रहते हुए, ट्रंप की कैबिनेट संभवतः वर्तमान संघर्षों को कम करने और पारंपरिक नीतियों में बदलाव की ओर बढ़ावा सकती है। गबार्ड के विचार अमेरिका की पुरानी नीतियों पर पुनर्विचार को बढ़ावा दे सकते हैं और अमेरिकी विदेश नीति में एक नई दिशा ला सकते हैं।

ट्रंप ने की गबार्ड की तारीफ : ट्रंप ने



व्यापक समर्थन मिला है। उन्होंने कहा, तुलसी हमारे सर्विधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगी और शांति के जरिए तात्कात को बढ़ावा देंगी। तुलसी हम सभी को गर्व महसूस कराएंगी। ट्रंप का यह फैसला एक साहस्रिक कदम माना जा रहा है, खासकर जब उन्होंने आपतौर पर अपने विश्वासपात्रों से भी इसका मत लेना चाहा है।

विदेशी हस्तक्रान्ति का आलाचना करता रहा है। उन्होंने बाइडेन को युक्तिक्रम को समर्थन और ओबामा प्रशासन की सीरिया में हस्तक्षेप की गलतता चिन्तित रखा है।

**रिपब्लिकन ने टंप के वफादार रिक स्कॉट को नकारा, जॉन थन को चना अमेरिकी सीनेट का नेता**

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सीनेट रिपब्लिकन पार्टी द्वारा दक्षिण डकोटा के सीनेट जॉन थून को नया नेता चुनना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम माना जा रहा है, खासकर तब जब आने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए सीनेट की भूमिका उप्राधिकारिताओं का निर्धारण हो रहा है। इस चुनाव में थून ने टेक्सास के अनुभवी सीनेटर जॉन कॉनिंग को हरा दिया, और फ्लोरिडा के सीनेटर रिक स्कॉट, जो ट्रंप के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं, को भी पीछे छोड़ दिया। रिक स्कॉट, जो प्रायोरिडा गवर्नर है और ट्रंप के प्रति अपनी निम्नोचकानी के लिए जाने जाते हैं, को ट्रंप समर्थकों द्वारा पसंदीदा उम्मीदवार माना जा रहा था। उन्होंने अपने के सभी प्रमुख नीतिगत एजेंडों को समर्थन किया था और उम्मीद जताई जा रही थी कि यह दोनों दलों के बीच एक समझौता हो सकता है।

में बढ़ जाएगा। हालांकि, ट्रंप ने स्कॉट की अलोकप्रियता को भांपते हुए उन्हें खुला समर्थन

**सीनेट का स्वतंत्र रुखः** : सीनेट, जो अपने स्वतंत्र और संरचनात्मक अधिकार को प्राथमिकता देती है, इस चुनाव में अपने पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने की ओर झुकी नजर आई। जॉन थून को सीनेट का एक पारंपरिक रिपब्लिकन नैता माना जाता है, और वे पुराने नेता मिच मैककोनेल के करीबी हैं, जिनका लंबे समय से सीनेट पर गहरा प्रभाव रहा है। यह चुनाव इस बात का संकेत भी है कि रिपब्लिकन पार्टी के कई सदस्य ट्रंप के प्रभाव को सीनेट में सीमित रखना चाहते हैं और एक अधिक स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। जॉन थून सीनेट में एक अनुभवी नेता हैं और वे रिपब्लिकन पार्टी के 'शीर्ष प्रांत' का दिंगे-



महत्वपूर्ण सदस्य माने जाते हैं। उनकी जीत से संकेत मिलता है कि पार्टी में अब भी परंपरावादी दृष्टिकोण का प्रभाव है और वे एक स्थिर नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, जो अत्यधिक पक्षपातपूर्ण रैतियों से जुड़े हैं।

नातियों से दूर रह।  
थून और कॉर्निन के खिलाफ ट्रूप के समर्थकों ने मजबूत अभियान चलाया। वे सीनेटरों पर व्यक्तिगत दबाव बना रहे थे ताकि ट्रूप समर्थित रिक स्कॉट को जीत मिल सके, लेकिन यह रणनीति उल्टी पड़ गई और कई सीनेटर इस दबाव से नाराज हुए। इस चुनाव का परिणाम दर्शाता है कि रिपब्लिकन पार्टी का एक बड़ा हिस्सा ट्रूप के अत्यधिक प्रभाव को संतुलित करना चाहता है। थून का नेतृत्व इस बात का संकेत हो सकता है कि पार्टी अगले कुछ वर्षों में किस प्रकार के फैसले लेगी और सीनेट में ट्रूप के पार्टी को चिपा दून दत्त प्रियंका राव जाएगा।

। स्वामी रामदेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल  
बरवाला में लगायी आर्ट एंड क्राफ्ट  
विज्ञान प्रदर्शनी

ऐसी ऐसी प्रदर्शनी व प्रतियोगिताओं में भाग लेने से बढ़ता है आत्मविश्वास -- डॉक्टर सुभाष संदूजा

( संस्कार उजाला

हरियाणा/ हिसार (गरिमा) : टोहाना मार्ग पर स्थित स्वामी रामदेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरवाला के प्रांगण में बाल दिवस के उपलक्ष्य में आर्ट एंड क्राफ्ट विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। स्कूल के प्रिंसिपल विकास चोपड़ा ने बताया कि इस प्रदर्शन में विद्यार्थियों ने पर्यावरण बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोबाइल फोन के दुष्प्रभाव, खेलों का महत्व, विज्ञान के लाभ और नशे से होने वाले दुष्परिणामों के अलग-अलग मॉडल बनाकर प्रदर्शित किए और अपनी अपनी कला व हुनर को प्रदर्शित कियो। स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष संदूजा, सत्या संदूजा, डॉक्टर विकास संदूजा व डॉक्टर अंजूम संदूजा ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विद्यार्थियों द्वारा कड़ी मेहनत व लगन से बनाए गए मॉडलों की सराहना की। स्कूल डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष संदूजा ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ ऐसी-ऐसी प्रदर्शनी व प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। ऐसी प्रदर्शनी व प्रतियोगिताओं में भाग लेने से अंदर छिपी हुई प्रतिभा उभरकर सामने आती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने विद्यार्थियों को बाल दिवस की बधाई दी। इस दौरान स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाओं को स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डायरेक्टर अजय सोनी, प्रिंसिपल विकास चोपड़ा, वाइस प्रिंसिपल नीलम सरदाना, पूनम चोपड़ा, धीरज हंदुजा, कुणाल सैनी, तरुण ढींगड़ा, गीता पिलानी व दर्शन ठिल्लों आदि मौजूद रहे।

**सड़क निर्माण में कोताही बरतने पर लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने एक्सईएन, एसडीओ व जेर्ड को किया सस्पेंड**

संस्कार उजाला

हरियाणा/हिसार (गरिमा) : हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने शुक्रवार को धिकताना गांव से धांसू गांव की सड़क निर्माण में कोताही बरतने पर एक्सईन् रजनीश कुमार, एसडीओ दलबीर सिंह राठी व जेई सुरेश कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं।

जनस्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने शुक्रवार को धिकताना गांव से धांसू गांव की बनी नई सड़क (5.440 कि. मी.) का निरीक्षण करते हुए यह निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने एसई अंजीत सिंह को सड़क के निर्माण में प्रयोग हुई सामग्री की जांच कराने तथा एजेंसी के खिलाफ अनुबंध के अनुसार सख्त कार्रवाही के निर्देश दिये। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में अच्छी क्वालिटी की सड़कों का निर्माण किया जाए। इन कामों को अच्छी क्वालिटी के साथ तय समय सीमा में पूरा किया जाए। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टैक्सपेरे के पैसों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी तरह की कोताही बदाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा, माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर मालवाल व एसई अंजीत सिंह उपस्थित रहे।

**जालिया के नए कार्यकारी अध्यक्ष  
मनोनीत हुए ज्यायाधीश भूषण  
दामकृष्ण गवई-इरन हसन**

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दृष्टिकोरी इस्म हसन ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। उन्होंने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पदी मुमुक्षु द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा की उप-धारा 2 के खंड बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत यह नियुक्ति की गई है। यह 11 नवंबर 2024 से प्रभावी है। इससे पहले न्यायमूर्ति बीआर एवं भानुराज युस्रीम कोट्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने बताया कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई पूरे भारत में सभी नागरिकों, विशेष रूप से समाज के हाशिए पर रहने वाले और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों को सुलभ और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के नालसा के मिशन का नेतृत्व करेंगे। उनके नेतृत्व से अनुच्छेद 39-ए के संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने के लिए नालसा की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने की उम्पाद है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि विर्त्तिय या सामाजिक बाधाओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वर्चित नहीं किया जाएगा।

**ਦਾਖਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਡਾਈ ਦਤਾਨੇਂ ਜੇ  
ਲੋਗਾਂ ਕੋ ਜਨਜਾਤੀਯ ਗੈਏਵ ਦਿਵਸ  
ਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਮਕਾਨਾਏਂ**

चंडीगढ़- हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारु दत्तात्रेय ने आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हरियाणा और पूरे देश के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी।

श्री दत्तात्रेय ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस, जो प्रतिवर्ष श्रद्धेय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान विरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, यह दिवस स्वतंत्रता संग्राम में भारत के आदिवासी समुदायों के अमूल्य योगदान और बलिदान की याद दिलाता है। जनजातीय समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, साहस और मनोवर्ती की साराहन करते हुए श्री दत्तात्रेय ने कहा कि भारत की प्रतिवध परंपराओं और मान्यताओं को संरक्षित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रखी है। राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस हमारे आदिवासी नेताओं और समुदायों का बहुदीर्घी और समर्पण का सम्पादन करने का अवसर है, जिन्होंने हमारे देश के सामाजिक और सांस्कृतिक तानेबानों को मजबूत करने का काम किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भगवान विरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर, 2024 से 15 नवंबर, 2025 तक वार्षिक समारोह का आयोजन करने का नियन्य लिया है, जो कि सराहनीय और जनजातीय समवय के लिए गौरव की बात है। 150वीं जयंती वर्ष के दौरान देशभर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को भगवान विरसा मुंडा के उत्तरीड़न व शैषण के खिलाफ प्रतिरोध व सघर्ष के जीवन को जानने का अवसर मिलेगा। दत्तात्रेय ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार आदिवासी समुदायों के कल्याण और उत्थान को बढ़ावा देने, सबका साथ-सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप समावेशी विकास और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं से भगवान विरसा मुंडा के आदर्शों से प्रेरणा लेने, राज्य और देश भर में सद्भाव, एकता और समृद्ध आदिवासी विरासत के प्रति सम्पादन को बढ़ावा देने का आग्रह किया।

# ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਪਦ ਦੀਪਾਨ ਦਿਨ, ਅਟੂਟ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ



वहीं, लगर में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। यह सिलसिला देर रात तक चला। रात को भी गुरु घर में गुरुग्रंथ साहिब के शब्दों का कीर्तन हुआ। दीवान सजाये गए। सिरोपा दे कर प्रबुद्ध जनों को सम्मानित किया। ।

सात  
सिंह  
महिं  
भाइ  
तथा

# **नरेंद्र बाली के जन्मदिन पर ५५ एकत्रिताओं ने किया एकत्रितान**

**दावन धाम की यात्रा करने से मन को शांति और  
खुण्ख-दमृद्धि की प्राप्ति होती है-कविन्द्र दाणा**

करनाल। कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के अवसर पर श्याम बालाजी दर्शन सेवा समिति व और से बृंदावन धान के लिए ब यात्रा रवाना हुई। इस मैके पर पू मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के प्रतिनिधि कविन्द्र राणा मुख्य अतिथि रूप में शिरकत समिति के प्रधान प्रमोद मंगला व उ प्रधान विकास गर्ग ने पटका फूलमालाएं पहनाकर कविन्द्र राणा का स्वागत किया। शहर के मुगु कनाल स्थित खेड़ा चौक से कविन्द्र राणा ने बस को झंडी देकर रवाना किया। इससे पर्व कविन्द्र राणा समिति के सदस्यों ने विधि-विधाय पूजा अर्चना की और नारियल फोड़कर बस यात्रा का शुभारंभ गय इस यात्रा में बड़ी संख्या श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इ अवसर पर कविन्द्र राणा ने कहा विव बृंदावन व अन्य धार्मिक यात्रा करने से मन को शांति मिलती है और घर में सुख-समृद्धि आती है श्री श्याम बालाजी दर्शन से समिति सराहनीय कार्य कर रही है हमें समीति के साथ जुड़कर परिव

सहित धार्मिक यात्रा जरूर करनी चाहिए। इस अवसर पर समिति के प्रथान प्रमोट मंगला ने बताया कि श्री श्याम बालाजी दर्शन सेवा समिति द्वारा हर माह बस यात्रा रवाना की जाती है। पिछले पांच वर्षों से निष्पत्ति भाव से श्रद्धालुओं को श्री खटू श्याम धाम, मेहंदीपुर बालाजी धाम, वृंदावन सहित अन्य धामों की यात्रा करवाई जा रही है। इस बार बस वृदावन धाम के लिए रवाना हो रही है। जिसमें भक्तजन बाके बिहारी मंदिर, राधाभल्लव लाल मंदिर, गोपीश्वर महादेव मंदिर, राधादामोदर, निधि वन, प्रेम मंदिर इस्कोन मंदिर आदि मंदिरों के दर्शन करेंगे। वहीं समिति के उपप्रधान विकास गांग ने बताया श्री श्याम बालाजी दर्शन सेवा समिति द्वारा हर माह श्रद्धालुओं को धार्मिक यात्रा करवाई जाती है। श्रद्धालुओं के लिए रहने व खाने पीने के लिए समिति की तरफ से उचित व्यवस्था की जाती है। इस अवसर पर मोहन लोदी, समिति के प्रधान प्रमोट मंगला, उप प्रधान विकास गांग, संजीव मित्तल, योगेन्द्र शर्मा, अनिल मित्तल, जरिन, रेनु मंगला, विपिन गुप्ता, ममता रानी व अशा रानी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

# **ਦਾਯ ਦਾਰੀਅ ਤੁਰ੍ਜਾ ਸਾਂਦਰਭ ਪੁਏਕਾਏ ਕੇ ਲਿਏ ਅਥ 26 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਕਾਈ ਆਵੇਦਨ-ਏਡੀਸੀ**

**एसपी चौहान ने हरियाणा में नशे जैसी बढ़त को लेकर विवाद किया।**

विकास की सीढ़ियों के चलते आपका ध्यान नशे जैसी सामाजिक बुराई की तरफ दिलाना चाहता हूं जो ना केवल हमारे युवाओं को अपनी प्रिप्टेशन में ले रही है बल्कि स्कूली बच्चों व कॉलेज के स्टूडेंट्स के जीवन को अपने काफिर पंजों से मिटाने को आतुर है। आज स्पष्टत तरेष के टप्पण आपे नशे के कारोबार को स्कूल व कॉलेजों की चारदीवारी में घुसकर करने लगे हैं। शिक्षा के मरियों को नशे जैसी बीमारी से बचाने के लिए गंभीर प्रयत्नों की ज़रूरत है। सेमे से दो प्राप्त्यार्थी हरियाणा व हरियाणा सरकार से विनम्र भाव से निवेदन करते हैं कि वे हरियाणा के विकास के साथ -साथ इस नशे के बढ़ते साप्राप्य पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तकि देश व ग्राम अंतर्राष्ट्रीय नवचेतना कहा कि वे जीवन में साथ अश खिलाफ आतुर है।

**धर्म का प्रचार करने के साथ  
संस्कृति का संवर्धन करना ही साधु  
का लक्ष्य-मानवी जी महाराज**

जन, जयपाल जन, सुनाल जन, सुनाता जन, नशा जन नातू जन सारता जन,

# दाई को जड़ से खत्म को को लिया पत्र

व सके। मुख्यमंत्री जी, हजारों  
त्र नशे की वजह से उजड़ रहे हैं,  
में नवचेतना मंच जिसमें कई  
राष्ट्रीय व शैक्षणिक संगठन जुड़े  
सरकार के साथ कधं से कधा  
र्य करने को तैयार हैं। आपके  
र्ण में हरियाणा प्रदेश से नशे की  
के लिए खत्म हो जाए और  
ीवन परिवार सहित खुशहाल हो,  
नशे के खिलाफ प्रदेश में गंभीर  
ई जानी चाहिए। नशे को सुपोर्ट  
नोगों के खिलाफ सख्त करवाइए  
। नशों पर प्रतिबंध के लिए  
लसी सख्ती से लगू हो, इस  
देश स्तर पर काम होना चाहिए।  
फा के मायने बताने के साथ-  
लता व सामाजिक बुराइयों के  
गातर अभियान चलाने वाले  
व के संयोजक एसपी चौहान ने  
हात हैं कि प्रदेश का युवाओं का  
दो बच्चे प्रतिवर्त्तक आप्ति

मां बाप, गांव, जिले, प्रदेश व देश का नाम  
रोशन करें और नशे जैसे कलंक से दूर रहें।  
मुख्यमंत्री व हरियाणा सरकार के सहयोग से  
नशे के खिलाफ नवचेतना मंच गंभीर मुहिम  
चलाने को तैयार हैं। बता दें कि एसपी चौहान  
द स्ट्राइलिंग मैन फिल्म के असल नायक  
एसपी चौहान पर बनी फिल्म नशे के करोबार  
के खिलाफ है और यह उनके जीवन की  
सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें उहने ने  
अपने स्कूली जीवन में स्टूडेंट्स और ग्रामीणों  
के साथ मिलकर करीब 4000 लोगों की  
शराब छुड़वाई थी। एसपी चौहान के जीवन  
पर लेखक संदीप सहिल द्वारा लिखी  
बायोप्रायासी संघर्ष को सलाम में नशे जैसी  
बुराएँ को प्रमुखता से उठाया गया, बाद में  
जिस पर अभिनेता जिम्मी शेरगिल, यशपाल  
शर्मा अभिनीत फिल्म बनी जिसे अमोजन व  
अन्य चैनलों पर करोड़ों लोग देख चुके हैं।  
फिल्म नशे के अलावा समाज के असली  
मुद्दों को दर्शकों के सामने आईने की तरह पेश  
करती है।

